Construction of sheds in Lodhi Colony

604. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the MINISTER OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether CPWD has permitted its contractors to construct sheds in different blocks of Lodhi Colony, for stoargc of scraps and old material;

(b) if so, the details of each such shed, block-wise, and since when these arc there;

(c) the conditios on which these constructions have been permitted and whether these are strictly followed;

(d) whether these sheds are causing insanitary and unhygienic conditions around and inconvenience to the allottees of the surrounding quarters;

(c) whether Government propose to remove these sheds, if so, by when each of these sheds arc proposed to be removed; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT AND THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) to (c) CPWD has reported that permission is granted to contractors under the provision of contract to construct sheds for execution of work. However, no permission is granted for construction of sheds for storage of scrap and old materials. There is one shed in each of the. Block No. 7, 9, 15, 16 & 17.' These sheds were constructed after June, 1995.

(d) No, Sir.

(e) The sheds are removed on completion of the work.

(f) The question does not arise, in view of (e) above.

J.J. Clusters of Delhi

605. SHRI O.P. KOHLI: Will the MINISTER OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether lakhs and lakhs of people in the Jhuggi-Jhopri clusters of Delhi are living in most pitiable conditions;

(b) whether Government propose to allot land for the construction* of multistorrcy dwelling units in order to relocate them so that they may live in neat, clean and hygienic environments; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT AND THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) to (c) It is estimated that there arc about 20-25 lakh jhuggic dwellers in about 4.80 lakh jhuggi house-holds in Delhi.

To improve the living conditions of the Slum/JJ Dwellers, the following thrccpronged strategy is being followed by the Government of NCT of Delhi through the Slum Department of the MCD:—

(i) Where the JJ dwellers arc residing since prior to 31.3.1990 on land urgently required by the land owning agency for the execution of a public purpose project, these JJ dwellers arc reloeatred elsewhere;

(ii) In-situ upgradation of the JJ colonics is resorted to where the land owning agency docs not need the land in the forcscable future and gives NOC to the effect that such clusters may be upgraded; and

(iii) Civic amenities like water supply, street lighting, road, storm water drain, etc. are provided in J J clusters, which do not fall in categories (i) and (ii) above.

At present relocation of eligible JJ dwellers is being undertaken by Government of NCT of Delhi on the concept of low-risc high density. Government of NCT of Delhi have been requested to examine the economics of the concept of

high rise high density vis-a-vis that of low rise high dcnity. Minimum basic civic facilities are being provided by Government of NCT of Delhi under the Plan scheme of Environmental Improvement of Urban Slums.

उत्तर प्रदेश में शहरों का विकास

606. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु प्रेषित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ख) प्रत्येत योजना के अंतर्गत विकसित किये जाने वाले शहरों के नामों और उनके विकास की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा इन योजनाओं पर कब तक निर्णय लिया जायेगा और निर्णय लेने में हो रहे विलमब के क्या कारण है?

जल-भूतल परिहवन मंत्री तथा शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री.टी.जी.वेकटरामण): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार को छोटे व मझोले कस्बों के समेकित विकास की स्कीम के तहत आने वाले कस्बों/शहरों में विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए सहायता दी गई है। इस स्कीम के तहत सहायता प्राप्त परियोजनाओं में मास्टर प्लान, सड़कों, स्थलों और सेवाओं को मजबूत करना, बस/ट्रक टर्मिनल का विकास, कचरा निपटान व्यवस्था, नगर/कस्बा पार्कों का विकास/मास्टर प्लान सड़कों के लिए पथ प्रकास व्यवस्था व अन्य जन-सुविधाएं यातायात सुधार व प्रबन्ध सेवाएं आदि शामिल है। विकास के लिए प्रस्तावित शहरों/कस्बों के नाम, सम्भावित परियोजना लागत तथा जारी केन्द्रीय राशि विवरण में दी गई है (नीचे देखिए) छोटे व मझोले कस्बों के समेवित विकास की मंजूरी समिति की 25.2.97 को हुई बैठक में कुछ अतिरिक्त कस्बों के प्रस्ताओं पर विचार हुआ था और वे प्रस्ताव, भारत सरकार के पास केन्द्रीय सहायता के लिए प्राप्त हुए थे।लेकिन पर्याप्त बजट के अभाव में इन कस्बों के लिए दन नहीं दिया जा सका। चालू वर्ष में इन अतिरिक्त कस्बों को केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम में शामिल करना उत्तर प्रदेश में चालू परियोजनाओं वाले कस्बों द्वारा धन की जरूरत तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर निर्भर करेगा। जब तक उ.प्र. सरकार चालू परियोजनाओं के लिए अपेक्षित धनराशि की सूचना नहीं देती तब तक यह बताना संभव नहीं है कि अतिरिक्त कसबों के लिए केन्द्रीय सहायता की मंजूरी के बारे में कब तक फैसला कर लिया जाएगा। अगर चालू परियोजनाओं के लिए दन की जरूरत इस राज्य के लिए नियत धनराशि अधिक है, तो अतिरिक्त कस्बों को केन्द्रीय सहायता में शामिल करना सम्भव नहीं होगा।

विवरण

(लाख रुपये)

वर्ष	कस्बे	नियत प्रदत्त राशि	राशि
1994-95	बस्ती	498.20	40.00
	फिरोजाबाद	366.13	33.00
	बड़ौत	300.00	36.00
	रामपुर	392.20	35.00
	बुढ़ाना	192.00	15.00
1995-96	अकबरपुर	204.10	30.00
	फरुखाबाद	283.27	27.00
	टांडा	179.19	27.00
	गोला गोरखनाथ	334.13	30.00
	खलीलाबाद	166.46	25.00
	उतरौला	186.29	28.00
	हरिद्वार	670.94	70.00
	मुरादनगर	218.27	30.00
	दादरी	172.75	26.00
	लोनी	190.30	30.00
	मुरादाबाद	766.27	90.00
1996-97	विलसी	118.56	16.00
	मगहर	88.52	11.00
	वांसी	174.47	30.00
	फफुंद	108.90	16.00
	फलियाकलां	113.07	18.00
	मलीहाबाद	85.63	13.00
	सहारनपुर	688.92	82.00
	फैजाबाद	337.47	45.00
	मानकपुर	110.86	16.00
	वरहतरागंज	85.69	14.00
	टूंडला	95.88	15.00
	अयोध्या	226.00	19.00